

कृषि संज्ञा

29 सितंबर २०२५



ASCI
Agriculture Skill Council of India

CEASI

CENTRES OF EXCELLENCE FOR
AGRICULTURE SKILLS IN INDIA



www.ceasi.in



प्रिय पाठकों,
हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र के माध्यम से आप तक पहुँच पाना हमारे लिए एक विशेषाधिकार है। यह समाचार पत्र CEASI की गतिविधियों की धड़कन को दर्शाता है, जो ASCI के संरक्षण में कार्यरत है, और हमारे सामूहिक सफ़र को कौशल विकास एवं सतत कृषि की दिशा में प्रतिबिंबित करता है। यहाँ साझा की जाने वाली हर कहानी हमारी टीमों, साझेदारों और कृषि समुदायों की समर्पित भावना का प्रमाण है। हमारा मिशन स्पष्ट है: किसानों और कृषि-पेशेवरों को वह कौशल, ज्ञान और तकनीक प्रदान करना जिसकी उन्हें बदलते समय में सफल होने के लिए आवश्यकता है। नवाचार और जमीनी स्तर पर जुड़ाव को मिलाकर, हम एक अधिक उत्पादक, लचीले और समावेशी कृषि क्षेत्र की नींव रख रहे हैं।
मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप इस समाचार पत्र को पढ़ें, सीखें और इसमें प्रस्तुत अवसरों में सक्रिय रूप से भाग लें। आपकी सहभागिता ही विचारों को प्रभाव में बदलती है।

डॉ. सतेंद्र सिंह आर्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी



प्रिय पाठकों,
CEASI का साप्ताहिक समाचार पत्र केवल गतिविधियों का सारांश नहीं है। बल्कि यह एक ऐसा मंच है, जहाँ विचारों का आदान-प्रदान, उपलब्धियों का उत्सव और भारतीय कृषि तथा इसके सहायक क्षेत्रों जैसे डेयरी, बागवानी, कृषि मशीनीकरण, जलवायु लचीलापन आदि के भविष्य के लिए हमारी साझा दृष्टि को और मजबूत किया जाता है। प्रत्येक अंक कृषि क्षेत्र और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से नवाचार, सहयोग और प्रगति की कहानियाँ लेकर आता है।

आगे बढ़ते हुए, हमारा ध्यान ज्ञान साझा करने, नवीनतम विकासों को सामने लाने, क्षमता निर्माण करने और सफलता की कहानियाँ हर स्तर पर किसान के खेत से लेकर नीति-निर्माताओं तक पहुँचाने पर रहेगा। ताकि आधुनिक उपकरण, तकनीकें और सर्वोत्तम प्रथाएँ उन तक पहुँच सकें जिन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है। मैं स्वीकार करता हूँ कि यह समाचार पत्र अभी अपने प्रारंभिक चरण में है। मैं पाठकों और हितधारकों से आग्रह करता हूँ कि वे इसमें प्रस्तुत पहलों, प्रशिक्षणों और अद्यतनों से जुड़े रहें, और ऐसी प्रमुख उपलब्धियों व घटनाओं को साझा करें जिन्हें यहाँ प्रकाशित किया जा सके। इसके दायरे, प्रकाशन की आवृत्ति, नए अनुभाग जोड़ने और सुधार के लिए आपके विचार इसे एक आदर्श पत्रिका बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे, जो हमें साथ मिलकर और अधिक मजबूत बनने के अवसर प्रदान करेगी।

जसवंत सिंह कालसी मुख्य परिचालन अधिकारी

हम कौन हैं:

“सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर स्किल्स इन इंडिया (CEASI)” एक स्वायत्त संस्था है, जो “एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया (ASCI)” के अधीन कार्य कर रही है। यह संस्था कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के तहत कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत किसानों, मजदूरी श्रमिकों, स्वरोजगार में लगे पेशेवरों, विस्तार कार्यकर्ताओं आदि के लिए कौशल विकास और क्षमता निर्माण का कार्य करती है।

CEASI कृषि के विभिन्न उप-क्षेत्रों में स्थापित उत्कृष्टता केंद्रों की शीर्ष संस्था है, जैसे कि:

- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डेयरी स्किल्स इन इंडिया (CEDSI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर स्किल्स इन इंडिया (CEHSI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फार्म मेकनाइजेशन स्किल्स इन इंडिया (CEFMI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट रेज़िलिएंट एग्रीकल्चर (CoE-CRA)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर (CoE-AI)

हम क्या करते हैं:

- **कौशल विकास और क्षमता निर्माण:** कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में हितधारकों की आवश्यकताओं के आधार पर क्षमता निर्माण।
- **ज्ञान प्रबंधन:** वर्कफोर्स मानकों को समर्थन देने हेतु QPs, NOS, स्किल गैप रिपोर्ट और न्यूज़लेटर्स का विकास।
- **अनुसंधान:** उद्योग की मांगों के अनुसार आवश्यकताओं की पहचान और कौशल अंतर को पाटने के लिए अनुसंधान।
- **नीति समर्थन और परामर्श सेवाएं:** नवाचार साझा करने और क्षेत्रीय चुनौतियों को हल करने हेतु नेटवर्क का निर्माण।

हमारा विज़न

एक स्वायत्त उत्कृष्टता संस्थान जो कृषि में उच्च कौशल युक्त कार्यबल विकसित करने के लिए समर्पित है, नवाचार, तकनीकी प्रगति और सतत प्रथाओं के माध्यम से भारतीय कृषि की समृद्धि और लचीलापन बढ़ाने के लिए कार्यरत है।

हमारा मिशन

राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर उन्नत कृषि पद्धतियों में कौशल विकास के लिए अग्रणी संगठन के रूप में उभरना, जो सततता, लाभप्रदता, क्षमता निर्माण, ज्ञान प्रसार, नीति समर्थन और नवाचार आधारित अनुसंधान के माध्यम से कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को प्रोत्साहित करता है।

CEASI का प्रभाव:

CEASI भारतीय कृषि में एक परिवर्तनकारी बदलाव ला रहा है, जो व्यक्तियों को सशक्त बनाने, कौशल को निखारने और देशभर में समुदायों को उन्नत करने का कार्य कर रहा है।

- ▶ 15+ राज्य
- ▶ 15 एफपीओ को प्रशिक्षित और सहयोग प्रदान किया गया
- ▶ 20,000 कृषि / डेयरी पेशेवरों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया
- ▶ 5000+ उद्यमियों को प्रशिक्षित किया गया
- ▶ 3000+ महिलाओं को सशक्त बनाया गया
- ▶ 30,000+ जीवन को प्रभावित किया गया

पंजाब सरकार ने खरपतवार जलाने को रोकने और हरित खेती को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया



पंजाब सरकार ने किसानों में फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान शुरू किया है। कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडियन ने बताया कि राज्य ने सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) योजना तैयार की है।

अभियान में 50 प्रचार वैन, 444 नुक्कड़ नाटक और 12,500 दीवार चित्रों के माध्यम से जागरूकता फैलायी जाएगी। 3,300 से अधिक गांव स्तर और 296 ब्लॉक स्तर शिविर आयोजित किए जाएंगे। ASHA कार्यकर्ता घर-घर जाकर किसानों को जानकारी देंगे। स्कूल के छात्रों को निबंध, चित्रकला और वाद-विवाद प्रतियोगिताओं के माध्यम से पर्यावरण जागरूक

बनाने में शामिल किया जाएगा।

अधिकारियों के अनुसार 2018 से अब तक किसानों को 1.58 लाख CRM मशीनें प्रदान की गई हैं, जिससे खेत में आग लगने की घटनाओं में कमी आई है। 2024 में 10,909 खेत आग की घटनाएं हुईं, जो 2023 की 36,663 घटनाओं की तुलना में 70% कम हैं। अधिकारी उम्मीद कर रहे हैं कि तकनीक और समुदाय की भागीदारी से स्टॉबल जलाने की घटनाओं में और कमी आएगी, जिससे हवा साफ और मिट्टी स्वस्थ रहेगी।

महाराष्ट्र भारत का पहला एआई-पावर्ड खेती वाला राज्य बना



महाराष्ट्र ने MahaAgri-AI Policy 2025-2029 शुरू कर कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का व्यापक उपयोग शुरू किया है। यह ₹500 करोड़ की पहल किसानों की आय बढ़ाने, उत्पादकता सुधारने और सतत खेती को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है।

नीति में ड्रोन, रोबोटिक्स, IoT सेंसर और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग कर सटीक कृषि और बेहतर फसल प्रबंधन को प्रोत्साहित किया जाएगा। "विस्तार" नामक AI सेवा किसानों को मराठी में वास्तविक समय सलाह देगी। Agricultural Data Exchange (A-DeX) के माध्यम से मिट्टी, मौसम और बाजार की जानकारी उपलब्ध होगी।

ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी से फसल की स्थिति, सिंचाई और कीट नियंत्रण की निगरानी की जाएगी। ब्लॉकचेन तकनीक से निर्यात गुणवत्ता वाले उत्पादों की पारदर्शिता और ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित होगी।

नीति में चार AI प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। विदर्भ में "Cluster AI Farming" पायलट परियोजनाओं में किसान समूह मिलकर AI के सुझावों के अनुसार खेती करेंगे।

राज्य की यह पहल खेती को आधुनिक बनाने, पैदावार बढ़ाने और किसानों की आजीविका मजबूत करने में मार्गदर्शक बनेगी।

केरल कृषि विभाग ने ₹100 करोड़ की माइक्रो-इरीगेशन परियोजना शुरू की



केरल कृषि विभाग ने गर्मी के मौसम में पानी की कमी से निपटने के लिए ₹100 करोड़ की माइक्रो-इरीगेशन परियोजना शुरू की है। कृषि उत्पादन आयुक्त बी. अशोक ने प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना के तहत इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और व्यापक जनभागीदारी की आवश्यकता पर जोर दिया।

हालांकि केरल में पर्याप्त वर्षा होती है, प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता कम है। इस परियोजना में ड्रिप और अन्य जल-संरक्षण तकनीकें लागू की जाएंगी। परियोजना नारियल, केला, काजू और औषधीय पौधों जैसी फसलों के लिए क्लस्टर आधारित होगी। इसका लाभ लगभग 6,000 किसानों को

मिलेगा, जल हानि 70% तक कम होगी और खेती अधिक लाभदायक होगी।

इस पहल में तालाब, जलाशय और अन्य बुनियादी सिंचाई ढांचे का निर्माण किया जाएगा। किसानों को पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिसे केरल कृषि विश्वविद्यालय, स्थानीय कृषि अभियंता और सलाहकार संचालित करेंगे। आवेदन कृषि विभाग के माध्यम से किए जा सकते हैं। परियोजना का उद्देश्य राज्य में सिंचाई की प्रभावशीलता बढ़ाना और किसानों की आय में सुधार करना है।

उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 में कृषि क्षमता प्रदर्शित करेगा



उत्तर प्रदेश 25-29 सितंबर 2025 को ग्रेटर नोएडा में UP International Trade Show (UPITS) 2025 में अपनी पारंपरिक और आधुनिक कृषि तकनीकों को प्रदर्शित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे।

कृषि विभाग ने 1,000 वर्ग मीटर के प्रदर्शनी क्षेत्र में ड्रोन, स्मार्ट सिंचाई प्रणाली और सटीक कृषि उपकरण प्रदर्शित किए जाएंगे। 15 से अधिक किसान उत्पादक संगठन (FPO) अपने उत्पाद और तकनीकें प्रस्तुत करेंगे, जिससे किसान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खरीदारों से सीधे जुड़ सकेंगे।

पाँच प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय और IIT कानपुर शोध आधारित समाधान, प्रशिक्षण मॉडल और एग्री-टेक स्टार्टअप प्रदर्शित

करेंगे। 17 कृषि यंत्रीकरण कंपनियाँ, बीज, उर्वरक और कृषि संरक्षण कंपनियाँ ड्रोन स्प्रेयर और AI-आधारित निगरानी उपकरण दिखाएंगी।

अधिकारियों ने कहा कि यह मेला किसानों, शोधकर्ताओं और उद्योगों के लिए सहयोग और निवेश के अवसर प्रदान करेगा, और उत्तर प्रदेश को कृषि नवाचार में बढ़ते केंद्र के रूप में स्थापित करेगा।

हिमाचल प्रदेश ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में बागवानी नवाचारों को प्रदर्शित किया



हिमाचल प्रदेश ने अपनी समृद्ध बागवानी विविधता को वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में प्रदर्शित किया, जो 25-28 सितंबर को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। राज्य के बागवानी विभाग ने एक विशेष पवेलियन लगाया जिसमें सेब, पारसपिमस, कीवी, ड्रैगन फ्रूट, शहद, जूस, रेड राइस और विदेशी शिमला मिर्च जैसी प्रीमियम उपज को प्रदर्शित किया। इस कार्यक्रम में 1,700 से अधिक प्रदर्शक, 500 अंतरराष्ट्रीय खरीदार और 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

बागवानी निदेशक विनय सिंह, जिन्होंने शिमला के वरिष्ठ अधिकारियों और प्रगतिशील किसानों के साथ प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए नवाचार

और परंपरा के एकीकरण को उजागर किया। पवेलियन में ब्लूबेरी क्रश, सीबकथॉर्न शॉट्स, पेटेंटेड गूछी और रेड राइस चाय, विशेष शहद, मोमबत्ती और लेमनग्रास तेल जैसी मूल्य-वर्धित उत्पादों ने विशेष ध्यान आकर्षित किया। वर्टीबूम द्वारा कॉर्डिसेप्स की खेती ने भी वैश्विक स्तर पर रुचि खींची।

एपीडा के समर्थन से, प्रतिनिधिमंडल ने अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के साथ बातचीत की, किसानों के उत्पादक संगठनों को मजबूत करने, शीत भंडारण का विस्तार करने और हिमाचल की उपज को वैश्विक बाजार की मांगों के अनुरूप बनाने पर जोर दिया, ताकि किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके।

संरक्षित खेती ने प्रयागराज को फ्लोरिकल्चर निर्यात केंद्र में बदल दिया



प्रयागराज का बागवानी क्षेत्र संरक्षित खेती के तरीकों, जैसे पॉलीहाउस और नेट हाउस, को अपनाने के साथ एक रूपांतरण देख रहा है, जिससे किसानों की आय और निर्यात क्षमता में वृद्धि हुई है। बागवानी विकास मिशन के तहत, पिछले वर्ष छह पॉलीहाउस और दो नेट हाउस स्थापित किए गए, जिसमें किसानों को 50% सरकारी सब्सिडी मिली। चार पॉलीहाउस फ्लोरिकल्चर पर केंद्रित हैं, जहां उच्च गुणवत्ता वाले फूल जैसे स्थानीय रूप से लोकप्रिय 'टॉप सीक्रेट' गुलाब और डेज़ी उगाए जाते हैं, जबकि दो नेट हाउस ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए उपयोग किए जाते हैं।

जिले के अधिकारियों के अनुसार, ये उच्च-तकनीकी संरचनाएं

नियंत्रित वातावरण प्रदान करती हैं, जिससे अस्थिर मौसम के बावजूद लगातार फसल की उपज सुनिश्चित होती है। अब ये फूल रूस और मध्य पूर्व के बाजारों में निर्यात किए जा रहे हैं, जिससे प्रयागराज एक उभरता हुआ फ्लोरिकल्चर हब बन गया है। हरवारी लाखापुर के किसान जिज्ञासु मिश्रा जैसे किसानों ने पॉलीहाउस खेती का उपयोग अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने के लिए किया, उच्च मांग वाले गुलाब उगाए और आय में महत्वपूर्ण वृद्धि की। यह पहल क्षेत्र में स्थायी और लाभकारी बागवानी के लिए एक मॉडल स्थापित कर रही है।

हिसार के किसान ने पारंपरिक फसलों से लाभकारी बागवानी की ओर किया कदम



हरियाणा के हिसार जिले के परभुवाला गाँव के किसान शिव शंकर खोवाल ने अपनी कृषि यात्रा को पारंपरिक फसलों जैसे धान और कपास से उच्च मूल्य वाली बागवानी की ओर बदल दिया है। 2005 में दो एकड़ में अमरूद की खेती से शुरुआत करते हुए खोवाल ने प्रति एकड़ 2.5 लाख रुपये कमाए और धीरे-धीरे 21 एकड़ में किन्नू, नींबू, बेर, मौसमी संतरा और खजूर की खेती की, जिसमें ड्रिप इरिगेशन का उपयोग किया गया।

2020 में उन्होंने अतिरिक्त पाँच एकड़ जमीन खरीदी, जिससे कुल फार्म का आकार 25 एकड़ हो गया, और नेट हाउस में सब्जियों की खेती शुरू की। 2024 तक उन्होंने केवल एक

एकड़ में बेल पेपर की खेती से 25 लाख रुपये कमाए, जिससे इस साल उन्होंने अपने नेट हाउस के सभी चार एकड़ में बेल पेपर लगाया और दिल्ली के आजादपुर बाजार में बिक्री के लिए तैयार किया।

खोवाल की सफलता बागवानी और संरक्षित खेती की लाभकारी संभावनाओं को उजागर करती है, यह दिखाती है कि रणनीतिक फसल विविधीकरण से किसानों की आय में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है और पारंपरिक फसलों पर निर्भरता कम हो सकती है।

कर्नाटक के डोड्डासगेरे बॉटनिकल गार्डन में जैव विविधता में वृद्धि



कर्नाटक के तुमकुरु में स्थित डोड्डासगेरे बॉटनिकल गार्डन, जिसे बेंगलुरु के लालबाग के मॉडल पर तैयार किया गया है, में जैव विविधता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है। मार्च 2025 में किए गए एविफौना सर्वे में 75 पक्षी प्रजातियां दर्ज की गईं—जो 2021 की 35 प्रजातियों से बढ़कर हैं—जिसमें दो निकट-आवश्यक और एक संवेदनशील प्रजाति शामिल है, साथ ही पांच लंबी दूरी के शीतकालीन प्रवासी भी पाए गए।

बागवानी विभाग द्वारा अपने नियोजित 228 एकड़ में से 120 एकड़ पर विकसित यह गार्डन अब लगभग 80 पक्षी प्रजातियों और लगभग 50 पशु, सरीसृप, तितलियों और मधुमक्खियों की प्रजातियों का घर बन गया है। 14 एकड़ में एम्फेसिस और

बेंगलुरु के यूनाइटेड वे के समर्थन से किए गए वृक्षारोपण प्रयासों में 77 स्थानीय पेड़ों के 1,00,000 पौधे लगाए गए, जिससे एक घना शुष्क पर्णपाती जंगल पुनः सृजित किया गया।

इस पार्क के 17 ब्लॉकों में बर्ड ब्लॉक, फ्रेग्रेस ब्लॉक, पामेटम और लगभग 400 फल देने वाले पौधों वाला न्यूट्रिशन गार्डन शामिल हैं। यह पहल कार्बन संकुलन, ऑक्सीजन उत्पादन, मिट्टी और जल संरक्षण, और वन्य जीवन के लिए आवास बढ़ाने पर केंद्रित है, जिससे यह गार्डन कर्नाटक में पारिस्थितिक पुनर्स्थापन और बागवानी उत्कृष्टता के लिए एक मॉडल स्थापित करता है।

बनास डेयरी ने एआई तकनीक से 30% मीथेन उत्सर्जन घटाने की पहल की



एशिया की सबसे बड़ी डेयरी सहकारी संस्था बनास डेयरी ने विश्व का सबसे बड़ा मीथेन कटौती कार्यक्रम शुरू किया है। बनास मीथेन प्रबंधन कार्यक्रम (BMMP) के तहत हर वर्ष लगभग 30 लाख पशुओं से होने वाले मीथेन उत्सर्जन को 30% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पहल का नेतृत्व चेयरमैन शंकर चौधरी कर रहे हैं, जो भारत को सतत डेयरी प्रथाओं में अग्रणी बना रहा है।

यह कार्यक्रम eVerse.AI की उन्नत जलवायु तकनीकों पर आधारित है, जिनमें कनेक्टेडकाउ और ग्रीनकाउ डिजिटल MRV सिस्टम शामिल हैं। ये प्लेटफॉर्म पशुधन उत्सर्जन की निगरानी, सत्यापन और नियंत्रण करते हैं। साथ ही, प्राकृतिक

पौध-आधारित फीड एडिटिव्स और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम को जोड़कर दूध उत्पादन में 10-12% तक वृद्धि की संभावना है।

मीथेन, जो कार्बन डाइऑक्साइड से 80 गुना अधिक प्रभावशाली ग्रीनहाउस गैस है, वैश्विक तापमान वृद्धि की बड़ी वजह है। महाराष्ट्र मीथेन मिशन से सिद्ध रणनीतियों को अपनाकर, बनास डेयरी ने एक वैश्विक मानक स्थापित किया है, जो किसानों की आय और पर्यावरणीय जिम्मेदारी दोनों को मज़बूत करता है।

पंजाब सरकार ने वेरका डेयरी उत्पादों के दाम घटाए, महंगाई से मिलेगी राहत



पंजाब सरकार ने महंगाई से जूझ रहे परिवारों को राहत देने के लिए वेरका डेयरी उत्पादों के दामों में बड़ी कटौती की है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में लिए गए इस निर्णय के तहत, घी की कीमतों में ₹30-35 प्रति किलोग्राम और पनीर की कीमतों में ₹15 प्रति किलोग्राम की कमी की गई है। इससे पूरे राज्य में उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा और आवश्यक खाद्य पदार्थों का बोझ कम होगा।

यह कदम उपभोक्ता कल्याण को प्राथमिकता देने और सहकारी डेयरी मॉडल को मज़बूत करने की सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। सस्ती दरों पर डेयरी उत्पाद उपलब्ध कराने से गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को बड़ी

राहत मिलने की उम्मीद है, जो अपनी आय का बड़ा हिस्सा भोजन पर खर्च करते हैं।

दरों में कमी से मांग बढ़ने की संभावना है, जिससे वेरका की बिक्री में इजाफा होगा। इससे किसानों की आय भी मज़बूत होगी और सहकारी संस्थानों को बल मिलेगा। साथ ही, बढ़ी खपत से राज्य की कर राजस्व आय में वृद्धि होने की उम्मीद है, जो पंजाब के दीर्घकालिक विकास एजेंडे को समर्थन देगी।

भारत में पहला राष्ट्रीय चीज़ महोत्सव: डेयरी नवाचार और विविधता का जश्न



गुजरात के एनडीडीबी, आनंद में फर्स्ट इंडियन चीज़ फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया, जो देश के डेयरी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। यह महोत्सव इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की इंडियन नेशनल कमेटी और पशुपालन एवं डेयरी विभाग के संयुक्त प्रयास से आयोजित किया गया।

महोत्सव का उद्देश्य भारतीय चीज़ में नवाचार को बढ़ावा देना और गुणवत्ता तथा बाज़ार क्षमता को विकसित करना था। इस अवसर पर 59 तरह की चीज़ प्रदर्शित की गईं, जिनमें सहकारी समितियों, स्टार्टअप्स और कारीगर उत्पादकों ने हिस्सा लिया।

कार्यक्रम में प्रतियोगिताएं, प्रदर्शनियां और सेमिनार शामिल थे, जिनमें उत्कृष्ट चीज़ निर्माण को सम्मानित किया गया। बेंगलुरु

मिल्क यूनियन लिमिटेड को रिपेंड चeddar के लिए और Vivanda Gourmet को गैर-दुग्ध चीज़ और नवाचार के लिए पुरस्कार मिला।

एनडीडीबी के अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह ने संगठित चीज़ क्षेत्र का विस्तार महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के लिए नए अवसर प्रस्तुत करता है। कार्यक्रम ने शहरी भारत में चीज़ की बढ़ती मांग और संभावित दो अंकीय वृद्धि पर भी ध्यान केंद्रित किया।

दिल्ली की डेयरी क्षेत्र में हरित ऊर्जा को बढ़ावा



दिल्ली की मुख्यमंत्री गुप्ता ने नांगली डेयरी में शहर के पहले बड़े पैमाने पर बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया, जो सतत कचरा प्रबंधन और हरित ऊर्जा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 2.72 एकड़ में फैले इस संयंत्र की क्षमता प्रतिदिन 200 टन गोबर और जैविक अपशिष्ट को संसाधित करने की है, जिससे शहरी सफाई और कृषि अपशिष्ट दोनों चुनौतियों का समाधान होगा।

संयंत्र से प्रतिदिन लगभग 14,000 घन मीटर कच्चा बायोगैस उत्पन्न होगा, जिसे शुद्ध कर 5.6 टन संकुचित बायोगैस (CBG) में परिवर्तित किया जाएगा। यह ऊर्जा सीधे इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) को प्रदान की जाएगी। संयंत्र से उत्पन्न पोषक

तत्वों से भरपूर खाद कृषि के लिए उपयोगी होगी, जिससे सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली प्रतिदिन लगभग 1,500 टन गोबर उत्पन्न करती है, और ऐसे और भी प्रोजेक्ट्स की आवश्यकता है। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरित ऊर्जा दृष्टिकोण के अनुरूप है और डेयरी अपशिष्ट प्रबंधन के साथ नवीनीकृत ऊर्जा उत्पादन में वैश्विक मॉडल स्थापित करती है।

पीएम-किसान: बाढ़ प्रभावित तीन राज्यों के किसानों को ₹540 करोड़ वितरित



केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए पीएम-किसान योजना के अगस्त-नवंबर किस्त के तहत ₹540 करोड़ जारी किए। इस किस्त का उद्देश्य उन किसानों को विशेष रूप से प्राथमिकता देना था जो हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलनों से गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं।

किसानों को इस योजना के तहत कुल ₹6,000 तीन समान किस्तों में चार-मासिक चक्रों—अप्रैल-जून, अगस्त-नवंबर और दिसंबर-मार्च—के माध्यम से वितरित किए जाते हैं। इस बार की ₹2,000 की किस्त कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जारी की गई। इस वित्तीय सहायता से प्रभावित किसानों को बुनियादी जरूरतों और आगामी फसल के लिए बीज एवं कृषि

इनपुट खरीदने में मदद मिलेगी।

त्रिची जिले में 28 किसान कल्याण केंद्र स्थापित किए जाएंगे



त्रिची जिले में कृषि और बागवानी विभाग मुख्यमंत्री किसान कल्याण सेवा केंद्र योजना के अंतर्गत 28 किसान कल्याण केंद्र (FWCs) स्थापित कर रहे हैं। इन केंद्रों में कुल निवेश ₹4.2 करोड़ है, जिसमें से ₹1.26 करोड़ सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य विशेष रूप से कृषि स्नातकों के बीच कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देना है।

किसान कल्याण केंद्र (FWCs) ऐसे हब के रूप में काम करेंगे जहाँ किसान कृषि इनपुट, नई तकनीक और विशेषज्ञ परामर्श प्राप्त कर सकेंगे। त्रिची के 28 केंद्रों में से 16 केंद्रों को कृषि विभाग और 12 केंद्रों को बागवानी विभाग द्वारा समर्थित किया जाएगा। बैकएंड सब्सिडी के रूप में ₹10 लाख मूल्य वाले केंद्रों के लिए ₹3 लाख और ₹20 लाख मूल्य वाले केंद्रों के लिए

₹6 लाख प्रदान किए जाएंगे।

राज्य स्तर पर, इस पहल के तहत 1,000 FWCs का निर्माण किया जाएगा, जिसमें कुल सब्सिडी ₹42 करोड़ होगी, ताकि प्रतिवर्ष बढ़ रहे कृषि स्नातकों और डिप्लोमा धारकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए उनका सशक्तिकरण किया जा सके।

महाराष्ट्र के स्कूल छात्रों को अगले साल से खेती के बारे में सीखने का अवसर



जून 2026 से, महाराष्ट्र राज्य शिक्षा विभाग स्कूल छात्रों के लिए एक कृषि पाठ्यक्रम शुरू करेगा, जिसका उद्देश्य खेती में व्यावहारिक सीखने और सहकारी शिक्षण पद्धतियों को बढ़ावा देना है। राज्य शिक्षा मंत्री पंकज भोयर द्वारा घोषित इस पाठ्यक्रम में मिट्टी विज्ञान, फसल उत्पादन, सिंचाई, कृषि प्रौद्योगिकी, पौध संरक्षण, बागवानी और पशुपालन सहित विभिन्न विषय शामिल होंगे।

इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक और आधुनिक खेती के तरीकों के बीच सेतु बनाना है, साथ ही स्थानीय ग्रामीण परंपराओं, कला और भूगोल को पाठ्यक्रम में शामिल करना है। यह पहल छात्रों में कृषि के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों जैसे कृषि पर्यटन में

पेशेवर मार्ग तैयार करने के लिए डिज़ाइन की गई है।

विशेषज्ञ एक व्यापक, तकनीकी-संवर्धित पाठ्यक्रम बनाने में शामिल होंगे, जो नई पीढ़ी को खेती से जोड़ता है और कृषि प्रथाओं के वैज्ञानिक समझ को बढ़ावा देता है।

भारत और रूस कृषि क्षेत्र में सहयोग मजबूत करेंगे



नई दिल्ली: कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 26 सितंबर को रूस के उप प्रधानमंत्री श्री दिमित्री पाटुशेव से कृषि सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।

बैठक में कृषि उत्पादों के व्यापार को बढ़ाने, बाजार पहुंच सुधारने और तकनीकी सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों पक्षों ने साझेदारी को औपचारिक रूप देने के लिए MoU पर विचार किया और बीज ट्रेसबिलिटी, तकनीकी सहयोग और नवाचार परियोजनाओं का सुझाव दिया।

श्री चौहान ने भारत की प्राथमिकताओं जैसे खाद्य सुरक्षा, किसानों की आय में वृद्धि और सुरक्षित भोजन की उपलब्धता पर जोर दिया। श्री पाटुशेव ने भारत-रूस के कृषि व्यापार को मजबूत करने की रूचि दिखाई।

दोनों देशों ने शैक्षणिक आदान-प्रदान, छात्रवृत्ति और अनुसंधान सहयोग पर भी चर्चा की। बैठक में कृषि मंत्रालयों, अनुसंधान संस्थानों और दूतावासों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। यह बैठक दोनों देशों की दीर्घकालिक सहयोग प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

अयोध्या में शाश्वत मिठास पहल के तहत सतत गन्ना खेती की तकनीक का प्रदर्श

शाश्वत मिठास पहल के तहत, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फार्म मेकेनाइजेशन स्किल्स इन इंडिया (CEASI) ने UPL SAS लिमिटेड के सहयोग से अयोध्या में सतत गन्ना खेती को बढ़ावा दिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों से अवगत कराना है, जो उत्पादन बढ़ाने के साथ प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशीलता बढ़ाती हैं।

अब तक, 500 किसानों का सर्वेक्षण किया गया है, जिनमें 90 असंगठित और 3 संगठित किसान समूह शामिल हैं, ताकि मौजूदा खेती की प्रथाओं को समझा जा सके और सुधार के क्षेत्र पहचाने जा सकें। इसके आधार पर गांव स्तर पर प्रदर्शन पोट लगाए गए हैं, जहां जल उपयोग की दक्षता, मिट्टी की सेहत और जैविक उर्वरकों के उपयोग जैसे सर्वोत्तम उपाय

दिखाए जा रहे हैं।

हाल ही में, एक मॉडल पोट पर किसान फील्ड डे आयोजित किया गया, जहां किसानों ने नियंत्रण पोट के साथ तुलना की। ZEBA तकनीक का प्रदर्शन बेहतर फसल वृद्धि, मिट्टी में नमी बनाए रखने और सिंचाई की आवश्यकता कम करने में सहायक साबित हुआ। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक किसानों ने भाग लिया और सतत व जल-संवेदनशील खेती अपनाने में गहरी रुचि दिखाई। UPL, KM शुगर मिल्स और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन (FPOs) जैसे प्रमुख हितधारकों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया, जो गन्ना क्षेत्र में पर्यावरणीय स्थिरता और समावेशी विकास की साझा दृष्टि को मजबूत करता है।



हरियाणा में EKL CSR फाउंडेशन के सहयोग से FPO नेतृत्व क्षमता सशक्त बनाने का कार्यक्रम

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फार्म मेकेनाइजेशन स्किल्स इन इंडिया (CEFMI) ने एसकॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड (EKL) के सहयोग से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एसकॉर्ट्स कुबोटा एडवांस्ड फार्मिंग इंस्टिट्यूट (EKFAI) में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन्स (FPOs) के लिए 3-दिवसीय रेजिडेंशियल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम 15 से 17 सितंबर 2025 तक दो बैचों में आयोजित किया गया और इसमें 35 FPOs के 75 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स (BoDs) और CEOs शामिल हुए, जो मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए। प्रशिक्षण का उद्देश्य FPOs की संगठनात्मक संरचना और शासन को मजबूत करना, कृषि यंत्रों की समझ बढ़ाना और

कृषि व्यवसाय के वित्तीय साधनों के बारे में जानकारी देना है। कार्यक्रम में नेतृत्व कौशल, बेहतर निर्णय लेने की क्षमता और सतत यंत्र समाधान पर विशेष ध्यान दिया गया, जिससे सदस्य किसानों को सीधे लाभ मिल सके।

इंटरएक्टिव सत्र, केस स्टडी और समूह चर्चाओं के माध्यम से FPO नेताओं को अनुभव साझा करने, संचालन चुनौतियों का समाधान खोजने और सामूहिक विकास के अवसरों का पता लगाने का अवसर मिला। रेजिडेंशियल प्रारूप ने गहन सीखने का माहौल बनाया, जिसमें सहकर्मी-से-सहकर्मी सीखने और सहयोग को बढ़ावा मिला।



असम में डेयरी और स्ट्रीट फूड हितधारकों के लिए गुणवत्ता, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डेयरी स्किल्स इन इंडिया (CEDSI) ने 16 सितंबर 2025 को अपने प्रशिक्षण केंद्र, c/o डायरेक्टरेट ऑफ डेयरी डेवलपमेंट, खानापारा, असम में गुणवत्ता, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा पर दूसरा बैच का जागरूकता कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया। इस कार्यक्रम में 30 प्रतिभागी शामिल हुए, जिनमें पारंपरिक मिठाई बनाने वाले, डेयरी सहकारी समितियों (DCS) के सदस्य और असम के स्ट्रीट फूड विक्रेता शामिल थे। सत्र का संचालन डॉ. मनशी दास, हेड, फूड टेक्नोलॉजी विभाग, असम स्किल यूनिवर्सिटी ने किया। उन्होंने खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन दिया। प्रतिभागियों को स्वच्छता प्रथाओं को लागू

करने, पारंपरिक मिठाइयों और डेयरी उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने और स्ट्रीट फूड को सुरक्षित रूप से संभालने के तरीके सिखाए गए।

इंटरएक्टिव प्रदर्शन में उचित भंडारण, स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वाद व पोषण बनाए रखने की तकनीक पर जोर दिया गया। प्रतिभागियों ने नियमों का पालन करते हुए ग्राहक विश्वास बढ़ाने के लिए व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किया। प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट हुआ कि कार्यक्रम स्थायी और सुरक्षित खाद्य प्रथाओं को बढ़ावा देने में सहायक है।

यह पहल CEDSI की असम में डेयरी और स्ट्रीट फूड क्षेत्र में कौशल विकास और क्षमता निर्माण के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है।





CEASI

CENTRES OF EXCELLENCE FOR
AGRICULTURE SKILLS IN INDIA



(CEASI), Unit No. 101, First Floor, Greenwoods
Plaza, Block 'B' Greenwoods City, Sector-45,
Gurugram, Haryana-122009



+91 74287 06078



info@cedsi.in



www.ceasi.in



@ceasi_india